

विचार

कितने जायज हैं ईवीएम पर विपक्ष के सवाल?

देश में प्रायः हर उस चुनाव के बाद विद्युतीय मतदान मशीन पर सवाल उठते रहे हैं, जब किसी भी विपक्ष की सरकार नहीं बन पाती। इस बार भी लोकसभा चुनाव के बाद देर से ही सही, लेकिन ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि अभी स्वर इसलिए भी धीमे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में विपक्ष के राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत बढ़ाकर एक मजबूत विपक्ष बनने का रास्ता तैयार कर लिया है। देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा दूश्य पहली बार दिख रहा है, जब विपक्ष सरकार बनाने से दूर रहकर भी अपनी विजय का अहसास करा रहा है। इसके विपरीत सत्ता पाने वाले राजग इस बात की समीक्षा कर रहा है कि उसकी सीटें कम कैसे हो गईं। जबकि यह समीक्षा विपक्षी दलों को करना चाहिए। खैरज बात हो रही थी ईवीएम की। इस लोकसभा चुनाव से पूर्व भी भाजपा के नेतृत्व में दो बार केंद्र में सरकार बनी, तब भी विपक्ष का यही मानना था कि ईवीएम की गड़बड़ी के कारण ही भाजपा ने विजय प्राप्त की है। हालांकि इन दस वर्षों के दौरान कई बार ऐसे चुनाव परिणाम भी आए हैं, जिसमें भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन विसंगति यही है कि इसके बाद विपक्ष की ओर से ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाए गए। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि विपक्ष की ओर से स्थिति देखकर ही सवाल उठाए जाते हैं। विपक्षी राजनीतिक दलों को ऐसा ही लगता है कि भाजपा के पास कोई जनाधार नहीं है, वे मात्र ईवीएम के सहारे ही जीतते हैं। जबकि विपक्ष के किसी राजनीतिक दल को किसी राज्य में सत्ता प्राप्त हो जाए तो फिर ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए जाते। हम जानते हैं कि विपक्ष को केवल भाजपा की जीत से परहेज है, वे भाजपा की जीत को पचा नहीं पाते, जबकि दिल्ली और पंजाब में आप आदमी पार्टी को छप्पर फाड़ समर्थन मिला था, लेकिन तब ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठा। हमें स्मरण होगा कि सन 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी दलों के अधिकतर नेताओं ने एक स्वर में ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। तब इन सवालों का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने सारे राजनीतिक दलों को बुलाया था कि ईवीएम को कोई हैक करके दिखाए। लेकिन उस समय ज्यादा विरोध करने वाले कोई भी राजनेता चुनाव आयोग के बुलावे पर नहीं पहुंचे। इसका तात्पर्य यही है कि विपक्ष के ईवीएम पर आरोप का कोई पृष्ठ आधार नहीं है। इस बार भी केवल आशंका के आधार पर ईवीएम को निशाने पर लाने की कोशिश की जाने लगी है। चुनाव परिणाम के बाद इस बात की पूरी संभावना बन रही थी कि इस बार ईवीएम को आड़े हाथ लिया जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग ने भी ईवीएम को लेकर उत्पन्न होने वाले भ्रम को दूर करने का प्रयास किया। लेकिन इतना होने के बाद भी यह भ्रम दूर नहीं हो सका और ईवीएम पर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। यह विवाद कितनी दूर तक जाएगा, यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन जब धूंआ उठने लगा है तो आग भी कहीं न कहीं लगी ही होगी। अब विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग और ईवीएम दोनों ही हैं। विपक्ष की ओर से यह कई बार कहा गया कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के संकेत पर कार्य करता है। वास्तविकता यह है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, जिस पर न तो किसी सरकार का कोई प्रभाव रहता है और न ही किसी राजनीतिक दल का। फिर भी चुनाव आयोग को क्यों विवाद में घसीटा जाता है। यहां यह भी बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर विदेश का कोई व्यक्ति या संस्था भारत के बारे में कोई सवाल उठाता है तो हमारे देश के कुछ लोग उस पर आँख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, जबकि हमारे देश के संस्थान केवल सफाई देते रहते हैं। अभी हाल ही में एलन मास्क द्वारा यह कहकर सनसनी फैलाने का ही काम किया है कि ईवीएम हैक हो सकती है। एलन मास्क ने यह बयान क्यों दिया, यह तो वही जानें, लेकिन विदेश के लोगों द्वारा भारत के बारे में ऐसे विवादित बयान कई बार दिए जा चुके हैं, जिसको आधार बनाकर भारत की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। पाकिस्तान की तरफ से तो मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए एक अभियान सा चलता दिखाई दिया

डा. रमेश ठाकुर
योग की आड़ में देश के भीतर बढ़ा धंधा पनप गया है। हानिगरों से लेकर कस्बों-गांवों में भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट, शिक्षण केंद्र, योग एवं चाहिए और न ही कोई इसकी किसी को कहाँ होना चाहिए। योग शरीर को चंगा रखने का मजबूत ध्यायर है और सदैव रहेगा। देखकर दुख होता है जब योग का शरीरिक जरूरतों से कहाँ ज्यादा मौजूदा समय में उसका वापसायिक, धार्मिक और सियासत में इस्तेमाल होता है। योग को अत्र स्वस्थ काया तक ही सीमित रखना चाहिए। उसकी आड़ में जनीतिक जरूरतें पूरी नहीं करनी चाहिए। योग गुरु कहलाकर मूचे संसार में प्रसिद्धि पा चुके बाबा रामदेव ने निश्चित रूप से योग प्रचार जबरदस्त तरीके से किया। इस दरम्यान उन्होंने बड़ा वसाय भी स्थापित किया। बाजार में हजारों प्रोडक्ट्स उत्तरकर नकी कंपनी का टर्नओवर लाखों-करोड़ों में नहीं, बल्कि अरबों पद्मनं गया है।

में पहुंच गया है। विवादों के इतर देखें तो बाबा रामदेव की कोशिशों की बदौलत ही योग को वैश्विक मान्यताएं मिली। केंद्र सरकार ने भी प्रचार-प्रसार में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। उसके बदले सरकार ने भी उनका फायदा चुनावों में जमकर उठाया। इस सच्चाई से भी इकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे योग विज्ञान का कुछ समय बीतने के बाद नुकसान हुआ। योग सत्ता पक्ष और विपक्ष में बंटकर भाजपा और कांग्रेस हो गया। जब पहला योग दिवस मना, तो कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने आयोजन का वॉकआउट किया। यहां तक उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने भी योग नहीं किया। लेकिन भाजपा ने हर्षोल्लास से मनाया। दरअसल, उनके मनाने का कारण क्या था, सभी को पता था। ठीक है, अगर विपक्षी दलों को बाबा रामदेव से कोई आपत्ति या ना-खुशी है, तो उनको योग को विरोध की केटेगरी में नहीं रखना चाहिए। बहरहाल, कोई कहे बेशक कुछ न, पर सियासत ने योग को धर्म से छोड़ने की भी कोशिशें की। योगासनों में भी धर्मों की एबीसीडी खोजी जाती है। दूसरा, सबसे दुःखद पहलू योग के साथ ये जुड़ा, योग का

परीक्षा पे चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री पेर लीक मुद्दे पर मंत्रियों और अधिकारियों से चर्चा क्यों नहीं करते?

नीरज कुमार दुबे
एक के बाद एक लीक होती परीक्षाओं के चलते देशभर में छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा उबाल ले रहा है। सवाल उठ रहा है कि यह कैसा तंत्र है जो प्रश्नपत्रों को लीक होने से नहीं रोक पा रहा है? सवाल उठ रहा है कि प्रश्नपत्र लीक होने पर परीक्षा रद्द कर देने और सीबीआई जांच बिठा देने से ही क्या छात्रों के समय और पैसे की बर्बादी रुक जायेगी? सवाल उठ रहा है कि क्या देश में परिश्रम, योग्यता और प्रतिभा के आधार पर कभी समान अवसर सुनिश्चित हो पाएंगे? हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और प्रश्नपत्र लीक करने वाले माफियाओं पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं?



मंत्रियों की जबान से देखते हैं, सख्त कार्रवाई करें, किसी को बरखा नहीं जायेगा जैसे बयान सुन सुन कर अब लोग उबर चुके हैं। बड़े-बड़े एसी कमरों में बैठने वाले मंत्रियों और अधिकारियों को शायद पता नहीं है कि बच्चों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए महां-महों कोचिंग सेंटरों में भेज कर मोटी फीस और ट्यूशन फीस पर लगने वाला भरी भरकम जी-एसटी देते देते अभिभावकों की कमर टूट जाती है, परीक्षा की तैयारी करते करते छात्रों की हालत खरब हो जाती है, बाबावार परीक्षा रह होने से छात्रों का समय और भविष्य को लेकर बनाई गई योजनाएं बाधित हो जाती हैं, इस सबसे छात्र अवसाद में आ जाते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर चुप्पी साध लेती है? इसके अलावा, पैसे वाले छात्र तो फिर भी अपने हक की लड़ाई के लिए अदालतों तक चले जाते हैं लेकिन बेचारे गरीब छात्र सिर्फ देखते रहे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के समय गरीब छात्र किसी तरह यात्र खर्चे का जुगाड़ कर परीक्षा केंद्र तक आते हैं और जब परीक्षा रह हो जाये तो उनके सामने कोई दृसग रस्ता भी नहीं रहता। दोबार परीक्षा होने पर परीक्षा शुल्क तक देने के उसके पास पैसे नहीं होते हैं इसलिए कई छात्र तो दोबार परीक्षा में भाग भी नहीं लेते। यह आश्वर्यजनक स्थिति है कि हम सर्जिकल और एअर स्ट्राइक के माध्यम से दुश्मन को उसके घर में छुस कर मारते हैं लेकिन अपने छात्रों के भविष्य से खिलावड़ करने वालों को सख्त सजा नहीं दिलवा पा रहे हैं। हम कहते हैं कि ये नया भारत है, कोई छेड़ा तो छोड़ो नहीं, लेकिन प्रश्नपत्रों के साथ छेड़गड़ होती जा रही है और हम कुछ कर नहीं पा रहे? हम आपको बता दें कि मोदी सरकार के आने से पहले तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए विभिन्न संस्थान थे, लेकिन उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाते द्वा गणित परीक्षा पर्सेंसी की स्प्राप्टन कर दी गयी। प्रप्त यह पर्सेंसी अपने आरम्भकाल से ही विवादों में रही है। प्रश्नपत्र लीक होते रहते हैं और अधिकारी हाथ पर हाथ धेर तब तक बैठे रहते हैं जब तक छात्र और अभिभावक सड़कों पर उत्तर कर हाँगामा नहीं करते। सरकार भी पूरे मामले पर तब तक चुप्पी बरतती है जब तक विषय पेपर लीक को बड़ा मुद्दा नहीं बना दे। प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी हर साल छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा तो करते हैं लेकिन सवाल उठता है कि वह पेपर लीक मुद्दे पर अपने मंत्रियों या अधिकारियों से चर्चा क्यों नहीं करते? बहरहाल, मोदी सरकार रण्यीय शिक्षा नीति तो ले आई लेकिन आप शिक्षा मंत्रालय के तमाम फैसलों को देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि इस सरकार की कोई शिक्षा नीति है नहीं बस मंत्री और अधिकारी प्रयोग पर प्रयोग किये या जा रहे हैं जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतान पड़ रहा है। हालिया लोकसभा चुनावों में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने मोदी सरकार से नागरिकी इसलिए भी जर्ता है क्योंकि वह पेपर लीक नहीं रोक पा रही है। जहां तक यूजीसी-नेट परीक्षा की बात है तो आपको बता दें कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ को लेकर उपजे विवाद के बीच, शिक्षा मंत्रालय ने रण्यीय परीक्षा एंजेसी (एनटीए) द्वारा आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा रह करने का बुधवार को आदेश दिया और मामले को गहन जांच के लिए सीबीआई को सौंपा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा, “यूजीसी को गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आईसीसी) की रण्यीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से परीक्षा के संबंध में कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। इन सूचनाओं से प्रथम दृष्टा संकेत मिला है कि उक्त परीक्षा की शुचिता से सम्बंधित किया गया।” मंत्रालय ने कहा, “परीक्षा प्रक्रिया में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि यूजीसी-नेट जन 2021 की परीक्षा रद्द कर दी जाए।”

तिब्बत को लेकर अमेरिका ने क्यों कर ली चाईना को घेरने की तैयारी?

नीरज कुमार दु

अमेरिका ने चीन को घेरने के लिए जो योजना बनाई है उसके तहत उसने तिब्बत को लेकर एक विधेयक पारित कर दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका की इस योजना को भारत का भी समर्थन है और इस आशंका के चलते चीन इस समय परेशान नजर आ रहा है। चीन को डर है कि यदि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाथ से तिब्बत फिसला तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है इसलिए वह अमेरिका को सीधे-सीधे और भारत को अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी देने में जुट गया है। लेकिन चीन की धमकियों से बेपरवाह नजर आ रहे अमेरिका ने तिब्बत को लेकर जो बड़ी फैसला किया है उस पर आगे बढ़ने के लिए वह अड़िगा नजर आ रहा है। यदि तिब्बत पर अमेरिकी नीति बदली तो क्षेत्र में इसका बड़ा असर पड़ने की संभावना है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पूर्व अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी और अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल मैककॉल के नेतृत्व में एक शिष्मंडल तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मुलाकात करने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचा तो चीन ने आंखें लाल कर लीं। लेकिन इसकी परवाह किये बिना नैन्सी पेलोसी ने भारत की धरती से चीन को तगड़ी चेतावनी दे डाली। हम आपको याद दिला दें कि 2022 में जब नैन्सी पेलोसी ताइवान के प्रति समर्थन जताने के लिए वहां की यात्रा पर थीं तब भी चीन ने गहरी नाराजगी जताई थी और अब जब पेलोसी तिब्बत के साथ समर्थन जताने के लिए दलाई लामा से मिलने पहुंची हैं तब भी चीन आग बबूला हो गया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात के बाद नैन्सी पेलोसी ने चीन को कड़े शब्दों में दिए गए संदेश में कहा कि परिवर्तन होने वाला है। उन्होंने कहा कि परम पावन दलाई लामा, ज्ञान, परंपरा, करुणा, आत्मा की पवित्रता और प्रेम के अपने संदेश के साथ लंबे समय तक जीवित रहेंगे और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। लेकिन आप (चीन के राष्ट्रपति) चले जाएंगे और कोई भी आपको किसी भी चीज का श्रेय नहीं देगा। पेलोसी की शी जिनपिंग के लिए आलोचनात्मक टिप्पणी तब आई जब वह चीनी राष्ट्रपति और दलाई लामा की आभा की तुलना कर रही थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दलाई लामा का संदेश, ज्ञान और करुणा हमेशा बनी रहेंगी। दूसरी ओर, यह धरती छोड़ने के बाद उनके (शी के) सभी काम किसी काम के नहीं रहेंगे। हम आपको बता दें कि मैककॉल के अलावा शिष्मंडल में अमेरिकी संसद के छह और प्रमुख सदस्य शामिल हैं जिनमें- नैन्सी पेलोसी, मैरिएनेट मिलर, ग्रेगरी मीक्स, निकोल मैलियोटैकिस, जिम मैकगर्वन और एमी बेरा शामिल हैं। यह प्रतिनिधिमंडल इसलिए धर्मशाला आया है क्योंकि हाल ही में अमेरिकी संसद ने एक विधेयक पारित किया है जिसमें मूल रूप से कहा गया है कि अमेरिका, तिब्बत के लोगों के साथ खड़ा है। माना जा रहा है कि इस प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि पेलोसी ने इस विधेयक के बारे में कहा है कि यह चीनी सरकार के लिए एक संदेश है कि इस मुद्दे पर हमारी सोच और समझ में स्पष्टता है।

हम आपको बता दें कि माइकल मैककॉल के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को हिमालयी शहर धर्मशाला पहुंचा था, जहां दलाई लामा 1960 के दशक से रह रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बत के लिए स्वायत्तता पर जोर दे रही निर्वासित तिब्बती सरकार के कार्यालयों का दौरा किया और फिर दलाई लामा से मुलाकात की। मैककॉल ने बाद में मीडिया को बताया कि चीनी अधिकारियों ने हमारे प्रतिनिधिमंडल को एक पत्र भेजा था जिसमें हमें यहां नहीं आने की चेतावनी दी गई थी। उन्होंने कहा कि लेकिन अमेरिका तिब्बत के आत्मनिर्णय के अधिकार के मामले में उसके साथ खड़ा है।

योग को न जोड़ें ल्यावसाय और राजनीति से?



व्यावसायिकरण कर दिया गया। कईयों की दुकानें योग की आड़ में चल पड़ी हैं। बड़े-बड़े प्रतिष्ठान, कॉलेज, स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो गए हैं, जहां योग सीखाने के नाम पर मोटा माल काटा जा रहा है। योग गुरुओं, एक्सपर्ट्स व प्रशिक्षकों की तो फौज ही खड़ी हो गई है। बड़े-बड़े नेताओं ने अपने लिए पर्मिनेंट योग प्रशिक्षक हायर किए हुए हैं। कुल मिलाकर योग को लोगां ने अब पूरी तरह से स्टेट्स सिंबल बना डाला है। यानी मध्यम वर्ग और गरीबों की पहुंच से बहुत दूर कर दिया गया है। योग विधा नई नहीं है, पांच हजार पर्व त्रिपुर परंपराओं से मिली अनमोल धरोहर जैसी है। ज्यादा पुराने समय की बात न करें, सिफ आजादी तक कि इतिहास खंगाले तो पता चलता है कि उस वक्त तक भी चिकित्सा विज्ञान ने उतनी सफलता नहीं पाई थी जिससे अचानक उत्पन्न हो वाली बीमारियों से तुरंत इलाज कराया जाए। उस वक्त भी जड़ी बुटियों और नियमित योगासन पर ही समूचा संसार निर्भर हुआ करता था।

अंग्रेजी दवाओं का विस्तार कोई चालीस-पचास के दशक से जोर पकड़ा है। तब मात्र एकाध ही फार्मा कंपनियां हुआ करती थीं जो अंग्रेजी दवाइयों का निर्माण करती थीं। विस्तार अस्पृष्टी के दशवर्ष

के बाद आरंभ हुआ। आज तीन से चार हजार के करीब फार्मा कंपनियां अंग्रेजी दवा बनाने में लगी हैं। बावजूद इसके योग का बोलबाला दिनों दिन बढ़ रहा है। जानकार बताते हैं कि अंग्रेजी दवाइयां तुरंत असर तो करती हैं। पर, शारीर की प्रतिरोधक क्षमता हिला देती है। शायद, इस सच्चाई से आम लोग अनभिज्ञ होते हैं कि बड़ी-बड़ी फार्मा कंपनियों के मालिक भी नियमित योगासन करते हैं। क्योंकि उनको योग के फायदे पता होते हैं। योग को एक नहीं, बल्कि हजारों बड़ी और गंभीर बीमारियों से लड़ने का हथियार माना गया है। वक्त फिर से पलटा है, इसलिए लोग धीर-धीरे पुरानी दवा पद्धतियों की ओर लौटने लगे हैं। सालों पुरानी हेल्प प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मरीज योग की मदद लेने लगे हैं। अनुभवी डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट को डेली रुटीन में योग शामिल करने की सलाह देते हैं। योग चिकित्सक मंगेश त्रिवेदी की माने तो ऐसे कई केस सामने आए हैं, जिसमें 15-20 साल पुरानी बीमारी को खत्म करने के लिए लोगों ने पहले योग की मदद ली और 3 से 4 महीने में इसका असर भी देखा है। बहरहाल, जरूरत इस बात नहीं है कि योग को सब रिटि 200 धार्म के लैक्या में जा सकिए जाए।

का है कि योग का राजनीतिक दल योग और योग को नियमित अपनाने वालों को अपना बॉट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग योग पर एक छत्र राज और अपनी ठेकेदारी भी जमाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, योग सबके लिए है और वह भी निःशुल्क। योग हमें ऋषियों-मुनियों द्वारा दी गई बेशकीयती सौगत है। हमारी धरोहर है जिसे हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़कर गए हैं। इसे सजोकर रखना हम सबका परमदायित्व बनता है। योग के फायदों से हम परिचित हैं। योग को लेकर हमें किसी लोभ-लालच में नहीं पड़ना चाहिए। योग करने वालों को भाजपा का कार्यकर्ता, रामदेव का अनुयायी या आरएसएस का शुभचिंतक नहीं समझना चाहिए। हालांकि, ऐसी मिथ्या अब लोगों से दूर हुई है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सभी अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हुए योग को अपनाएं। ‘विश्व योग दिवस’ का मकसद हममें योगासन के प्रति ललक पैदा करना और दूसरों को योग के लिए जागरूकता करना मात्र होता है। योग स्वस्थ शरीर का मुख्य सारथी है, इसे दूर न करें, नियमित अपनाएं।

नये सत्र में मेहनत से पढ़ाई कर लक्ष्य को प्राप्त करें: कलेक्टर भविष्य से भेंट कार्यक्रम में कलेक्टर पहुंचे कन्या हाई स्कूल धवारी

मीडिया ऑँडीटर, सतना निप्र। 'स्कूल चले हम' अभियान के तहत प्रवेशोत्सव के तीसरे दिन भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत कलेक्टर अनुराग वर्मा गुरुवार को शासकीय वार्षा हाई स्कूल धवारी पहुंचे औंच्छात्राओं से संवाद किया। कलेक्टर ने छात्र-छात्राओं के बीच पहुंचकर उहें अपनी ओर से कार्यालय, पेन, चॉकलेट और टॉफियां भेंट करनियमित रूप से स्कूल आये पर डीपीसी विष्णु त्रिपाठी, जनसंपर्क अधिकारी राजेश सिंह, शाला की प्राचीर राजीव श्रीवास्तव सहित शिक्षिकायें एवं छात्राओं उपस्थित किया। इस अवसर पर डीपीसी विष्णु त्रिपाठी, जनसंपर्क अधिकारी राजेश सिंह, शाला की प्राचीर राजीव श्रीवास्तव सहित शिक्षिकायें एवं छात्राओं उपस्थित किया।



जो कुछ भी सीखा जाता है, उससे ज्ञान और अनुभव बढ़ता है। अच्छे और बुरे ज्ञान की पहचान करें और जो अच्छाइयों का ज्ञान है उसे ही ग्रहण करें। कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा के लिए संसाधन महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि मेहनत और समर्पण की भावना महत्वपूर्ण होती है।

अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी अच्छा सीखें उसे अत्मसात करें। पढ़ाई सिफर नौकरी के लिए नहीं करें, नौकरी को बाय प्रोडक्ट के लिए नहीं करें। अद्यतन का उत्तर बनाने का है। अपने अच्छी कैरियर और भविष्य बनाने की बुनियाद होती है। हम जो भी सीखें उसे अपने जीवन में उतारें। अपने लिए आप जितना अच्छा कर सकेंगे, उसके परिवार, समाज, देश उतना ही बेहतर बनेगा।

कलेक्टर ने कहा कि यह समय आपकी जड़ों को मजबूत करने का है। अपने अच्छी कैरियर और भविष्य बनाने की बुनियाद होती है। हम जो भी सीखें उसे अपने जीवन में उतारें। अपने लिए आप पिछले सत्र में जो सुकाम हासिल नहीं कर पायें, उहें प्राप्त करें। सभी स्कूल खुल गए हैं और नए सत्र की सभी कक्षाएं विधिवत प्रारंभ की जा रही हैं।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज जिला स्तरीय कार्यक्रम शासकीय व्यंकट-1 सतना के पीछे के मैदान में होगा आयोजित

मीडिया ऑँडीटर, सतना निप्र। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने निर्माण विभागों एवं एजेंसियों से वर्तमान में जिले में चल रहे निर्माण और विकास के कार्यों को अधिकाधिक रूप से बरसात के पहले पूर्ण कर लेने के लिए निर्देश दिए हैं। उहेंने सड़कों के डामोरिकरण का कार्य भी एक-दो दिन के भीतर पूर्ण करा लेने को कहा है। कलेक्टर ने गुरुवार को ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जल निगम, लोक निर्माण, एसपीसआरडीसी, राहिंसिंग बोर्ड, पीआईयू, नर्मदा घाटी विकास के अधिकारियों की बैठक लेकर 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर सीधी जिला पंचायत संजना जैन भी उपर्युक्त रही।

22 जून को बाधित रहेगा विद्युत प्रवाह सतना 20 जून 2024/कार्यपालन अधिकारी (विद्युत) ने बताया कि 22 जून को 9 बजे से 11 बजे तक 132 केवी उपक्रेंट अमरपाटन से निकलने वाले 32 केवी मेनबेस पैडर एवं अन्य मेनटीरेस के कार्य में आयोजित होगा।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के

निर्माण के संबंध में जारी निप्र। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने निर्माण विभागों एवं एजेंसियों से वर्तमान में जिले में चल रहे निर्माण और विकास के कार्यों को अधिकाधिक रूप से बरसात के पहले पूर्ण कर लेने के लिए निर्देश दिए हैं। उहेंने सड़कों के डामोरिकरण का कार्य भी एक-दो दिन के भीतर पूर्ण करा लेने को कहा है। कलेक्टर ने गुरुवार को ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जल निगम, लोक निर्माण, एसपीसआरडीसी, राहिंसिंग बोर्ड, पीआईयू, नर्मदा घाटी विकास के अधिकारियों की बैठक लेकर 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर सीधी जिला पंचायत संजना जैन भी उपर्युक्त रही।

जल निगम के कार्यों की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि पूरे जिले में जल जीवन मिशन के

निर्माण कार्य में आयोजित होगा।

अनुदान पर कृशि यंत्र उपकरणों के लिये ई-पोर्टल पर आवेदन 26 तक

मीडिया ऑँडीटर, सतना निप्र। संचालनालय कृषि अधिकारीकी मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर सतना के लक्ष्य विधार्हण कर दिये गये हैं। स्थानक वृष्टि यंत्रों से संबंधित संस्थानों के विद्यार्थी भाग लेंगे। इसके साथ एवं अनुदान पर 26 जून तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर 27 जून 2024 को लॉटोरी के माध्यम से अनुदान पर कृषि यंत्र क्रय करने पोर्टल पर 26 जून तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।

हितग्राही का चयन किया जायेगा। निर्धारित लक्ष्यानुसार योग्य उपकरणों के लिये 9 का लक्ष्य है और इसके लिये 5 हजार रुपये के लिये 5-5 हजार रुपये की डीडी धरोहर राशि के रूप में देना होगा। सीड कम्प फर्टलाइजर, डिल/जीरो एवं स्वयं के बैंच खाते से धरोहर राशि के स्वयं की डीडी कम्प फर्टलाइजर, डिलरेड वेडलाइटर, रिजेक्टोर प्लाटर और मल्टीक्रॉट प्लाटर के लिये 7 का लक्ष्य है। इसके लिये 2 हजार रुपये की डीडी धरोहर के लिये मोबाइल नंबर 8224029722 पर संपर्क किया जा सकता है।

अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। इनमें कृषि यंत्र सीधे समाज के समय-सारों के लिये 9 का लक्ष्य है और इनमें कृषि यंत्रों के लिये 5 हजार रुपये की डीडी धरोहर राशि के रूप में देनी होती है। कृषक कम्प फर्टलाइजर, डिल/जीरो एवं स्वयं के बैंच खाते से धरोहर राशि के स्वयं की डीडी कम्प फर्टलाइजर, डिलरेड वेडलाइटर, रिजेक्टोर प्लाटर और मल्टीक्रॉट प्लाटर के लिये 7 का लक्ष्य है। इसके लिये 2 हजार रुपये की डीडी धरोहर के लिये मोबाइल नंबर 8224029722 पर संपर्क किया जा सकता है।

जबलपुर फेरलेन सड़क से जुड़ने का मानदण्डित परिक्रमा पथ, के लिए पीपीसी मोड पर होटल तथा अन्य पर्यटन सुविधाओं का निर्माण तकाल शुरू कराएं। विकास के कार्य डीपीआर में विकास के कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जबलपुर फेरलेन सड़क से जुड़ने का मानदण्डित परिक्रमा पथ, के लिए पीपीसी मोड पर होटल तथा अन्य पर्यटन सुविधाओं का निर्माण तकाल शुरू कराएं। विकास के कार्य डीपीआर में विकास के कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जबलपुर फेरलेन सड़क से जुड़ने का मानदण्डित परिक्रमा पथ, के लिए पीपीसी मोड पर होटल तथा अन्य पर्यटन सुविधाओं का निर्माण तकाल शुरू कराएं। विकास के कार्य डीपीआर में विकास के कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जबलपुर फेरलेन सड़क से जुड़ने का मानदण्डित परिक्रमा पथ, के लिए पीपीसी मोड पर होटल तथा अन्य पर्यटन सुविधाओं का निर्माण तकाल शुरू कराएं। विकास के कार्य डीपीआर में विकास के कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जबलपुर फेरलेन सड़क से जुड़ने का मानदण्डित परिक्रमा पथ, के लिए पीपीसी मोड पर होटल तथा अन्य पर्यटन सुविधाओं का निर्माण तकाल शुरू कराएं। विकास के कार्य डीपीआर में विकास के कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जबलपुर फेरलेन सड़क से जुड़ने का मानदण्डित परिक्रमा पथ, के लिए पीपीसी मोड पर होटल तथा अन्य पर्यटन सुविधाओं का निर्माण तकाल शुरू कराएं। विकास के कार्य डीपीआर में विकास के कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जबलपुर फेरलेन सड़क से जुड़ने का मानदण्डित परिक्रमा पथ, के लिए पीपीसी मोड पर होटल तथा अन्य पर्यटन सुविधाओं का निर्माण तकाल शुरू कराएं। विकास के कार्य डीपीआर में विकास के कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जबलपुर फेरलेन सड़क से जुड़ने का मानदण्डित परिक्रमा पथ, के लिए पीपीसी मोड पर होटल तथा अन्य पर्यटन सुविधाओं का निर्माण तकाल शुरू कराएं। विकास के कार्य डीपीआर में विकास के कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जबलपुर फेरलेन सड़क से जुड़ने का मानदण्डित परिक्रमा पथ, के लिए पीपीसी मोड पर होटल तथा अन्य पर्यटन सुविधाओं का निर्माण तकाल शुरू कराएं। विकास के कार्य डीपीआर में विकास के कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जबलपुर फेरलेन सड़क से जुड़ने का मानदण्डित परिक्रमा पथ, के लिए पीपीसी मोड पर होटल तथा अन्य पर्यटन सुविधाओं का निर्माण तकाल शुरू कराएं। विकास के कार्य डीपीआर में विकास के कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जबलपुर फेरलेन सड़क से जुड़ने का मानदण्डित परिक्रमा पथ, के लिए पीपीसी मोड पर होटल तथा अन्य पर्यटन सुविधाओं का निर्माण तकाल शुरू कराएं। विकास के कार्य डीपीआर में विकास के कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जबलपुर फेरलेन सड़क से जुड़ने का मानदण्डित परिक्रमा पथ, के लिए पीपीसी मोड पर होटल तथा अन्य पर्यटन सुविधाओं का निर्माण तकाल शुरू कराएं। विकास के कार्य डीपीआर में विकास के कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जबलपुर फेरलेन सड़क से जुड़ने का मानदण्डित परिक्रमा पथ, के लिए पीपीसी मोड पर होटल तथा अन्य पर्यटन सुविधाओं का निर्माण तकाल शुरू कराएं। विकास के कार्य डीपीआर में विकास के कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जबलपुर फेरलेन सड़क से जुड़ने का मानदण्डित प